



रोमन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय विश्व का पहला आधुनिक ऑर्निथॉलॉजिस्ट (पक्षी विज्ञानी) था। तेरहवीं सदी में उसने पक्षियों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया था। पक्षियों में उसकी गहरी रुचि थी, खासकर बाज में। उसे बाज पालने (फैल्कनरी) का शौक था और उसने पक्षियों पर एक किताब भी लिखी थी। फ्रेडरिक द्वितीय द्वारा लिखी किताब "आर्ट ऑफ हंटिंग विद बर्ड्स" को आधुनिक ऑर्निथॉलॉजी की पहली किताब तथा पक्षियों का पहला वैज्ञानिक अध्ययन व आधुनिक ऑर्निथॉलॉजी की शुरुआत माना जाता है। फ्रेडरिक अरस्तु के जीव वर्गीकरण से बेहद प्रभावित था। उसने अपनी किताब में भी अरस्तु का जिक्र किया था। अरस्तु ने पक्षियों को तीन वर्गों में बांटा था, जलचर, थलचर और उभयचर पक्षी। फ्रेडरिक ने इन वर्गों का, पक्षियों की खान-पान की आदतों के आधार पर और आगे वर्गीकरण किया। शोधकर्ता जॉनिस एम. ह्यू ने बताया कि फ्रेडरिक की रुचि पक्षी प्रवास में भी थी। उसकी किताब में प्रवास करने वाले पक्षियों की जानकारी भी है, कि वे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और प्रवास क्यों करते हैं। सामान्य तौर पर उसने भी यही बताया कि, पक्षी मौसम और भोजन की कमी के कारण दूसरी जगह जाते हैं, पर उसने यह भी बताया कि खास किस्म का भोजन पसंद करने वाले पक्षी मनपसंद भोजन की तलाश में दूर तक भी चले जाते हैं। जनवरी 1194 ईस्वी में जन्मा फ्रेडरिक द्वितीय बेहद प्रतिभाशाली था। उसे "स्टुपर गुडि" (विश्व का अजूबा) की उपाधि दी गई थी। उसे पोप से युद्ध करने के लिए भी जाना जाता है। उसने पोप से युद्ध कर इटली को पोप के शासन से मुक्त कराने का प्रयास किया था। वह सभी धर्मों का आदर करता था। उसने सिसली में विज्ञान व साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया।

राजे की यात्रा के तुरंत बाद शाह के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेश कार्यसमिति की बैठक और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को सम्बोधित करने 5 दिसंबर को जयपुर में

जयपुर, 25 नवम्बर (का.सं.)। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृहमंत्री अमित शाह के आगामी 5 दिसम्बर के जयपुर दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा के तुरन्त बाद अब शाह के दौरे को लेकर कई सियासी चर्चाएं चलने लगी हैं। जैसे कि क्या अब अमित शाह के दौरे के बाद प्रदेश भाजपा की राजनीति में सब कुछ ठीक हो जाएगा? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने जयपुर में एक प्रेस वार्ता में बताया कि

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को प्रदेश कार्यसमिति बैठक और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक 4 और 5

■ अमित शाह के मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और मिशन 2023 की विजय को लेकर मील का पत्थर साबित होगा: डॉ. पूनिया

दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगी गृहमंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को विशेष सत्र को सम्बोधित करेंगे और इसके बाद करीब 10 हजार जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। इस सम्मेलन में अमित

शाह पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान व उपप्रधान, सांसद, विधायक इत्यादि जनप्रतिनिधियों को सम्बोधित कर मार्गदर्शन देंगे। पूनिया ने बताया कि प्रदेश कार्यसमिति बैठक 4 दिसम्बर को शुरू होगी, जिसमें पार्टी की संगठनात्मक समीक्षा, आगामी कार्ययोजना, सम्पूर्ण किसान कर्जामाफी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था इन तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति और मिशन 2023 की विजय को लेकर विस्तृत चर्चा की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार को सफलतम 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसको लेकर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में भारी फेरबदल ?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवम्बर। राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत व्यस्त हो गये हैं।

वे चाहते हैं तथा उन्हें इस बात की जरूरत भी है कि नये और पुराने सभी मंत्रियों को नियंत्रण में रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित

■ नये पुराने मंत्रियों पर, सख्त निगाह रखने के लिए मु.मंत्री सही अफसर, सही मंत्री के साथ लगायेंगे।

■ जैसा कि विदित ही है, मु.मंत्री गहलोत राज्य में प्रशासन पर सख्त नियंत्रण रखते आए हैं। इसी प्रवृत्ति के अधीन अब मंत्रियों पर शिकंजा टाइट रखने के लिए मु.मंत्री सरकारी अधिकारियों का पुनः उपयोग करेंगे।

हो सके कि सरकार के सर्वसर्वों वे ही बने हुए हैं।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत राज्य के बड़े अफसरों, पुलिस तथा प्रशासन में बड़ी फेरबदल करके यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सही मंत्री के साथ सही अफसर लगाया जाए जिससे मंत्रियों पर नजर तथा उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।

सूत्रों का कहना है कि गहलोत अफसरशाही की सूची तैयार कर रहे हैं तथा उनमें से कुछ अफसरों को विभिन्न जिलों से राज्य की राजधानी में ला रहे हैं।

सर्वविदित है कि अशोक गहलोत अफसरशाही के माध्यम से राज्य, सरकार विभिन्न मंत्रियों तथा मंत्रालयों पर नियंत्रण रखते आये हैं तथा यह वैश्या राज्य के राजनेताओं के लिए चिंता का विषय रहा है।

'शहीद हुए आंदोलनकारियों को मुआवजा दें'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवम्बर। किसान-आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने गुरुवार को अपील जारी की कि 26 नवम्बर को दिल्ली की सीमाओं तथा राज्यों की राजधानियों में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया

जायेगा तथा शुक्रवार को अपना एक वर्ष पूरा कर रहा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तथा उन आधा दर्जन मॉर्गों को स्वीकार नहीं कर लेती, जो इस सप्ताह के शुरू में प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र में उठाई गई थी।

एस.के.एम. ने कहा है कि हजारों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ संयुक्त किसान मोर्चा ने यह मांग उठायी, तथा 26 नवम्बर को दिल्ली बॉर्डर पर शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की योजना बनाई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मेघालय में एक और झटका लगा कांग्रेस को

सत्रह विधायकों में से 12 ने कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल में शामिल होने की घोषणा की

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवम्बर। कांग्रेस को गुरुवार को उस समय एक बार फिर जबरदस्त धक्का लगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में पार्टी के 17 में से 12 विधायकों ने अपने इस निर्णय की घोषणा कर दी कि वे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस घटना के बाद, कांग्रेस मेघालय विधानसभा में तीसरे नम्बर पर पहुँच गई है, जबकि टी.एम.सी. मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने की स्थिति में आ गई है।

कांग्रेस को अलविदा कहने की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। रायबरेली सदर से पार्टी-विधायक अदिति सिंह जो गांधी परिवार के निकटस्थ मानी जाती थीं, भी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई थीं।

नेताओं के कांग्रेस छोड़कर जाने के संबंध में दो मुद्दे प्रासंगिक हैं। पहला, पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग आदतन

■ इस पलायन का एक मतलब यह भी है कि, पार्टी छोड़कर जाने वाले इन विधायकों में से शायद ही कोई शीघ्र ही कांग्रेस में पुनः लौटेगा।

■ पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि, जिस गति से ममता देश के विभिन्न राज्यों में अपना पार्टी का बोर्ड लगाने के प्रयास में हैं, उसी तरह केजरीवाल की भी दिल्ली में सरकार बना लेने के बाद, पंजाब, गुजरात आदि प्रदेशों में पार्टी का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा थी तथा उन्होंने मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव भी लड़ा था, पर ये प्रयास विफल होने के बाद वे दिल्ली में सिमट कर रह गये थे। कहीं ममता बनर्जी का भी यही हथ्रो तो नहीं होगा।

पार्टी बदलते रहने वाले लोग नहीं हैं, जो किसी भी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदल लिया करते हैं। ऐसी स्थितियाँ नगण्य रही हैं। दूसरा, जो लोग इस समय पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके निकट भविष्य में पार्टी में वापस आने की कोई संभावना नहीं है।

त्रिपुरा म्युनिसिपल चुनाव

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवम्बर। त्रिपुरा में गुरुवार को नगरीय चुनाव शुरू होने के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से कहा कि 20 नगरपालिकाओं में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सैन्ट्रल ऑर्डर पुलिस फोर्स (सी.ए.पी.एफ.) की दो टुकड़ियाँ भेजी जाएं।

जस्टिस डी. वाय. चन्द्रचूड और विक्रम नाथ की बेंच ने गुरुवार को केन्द्र

■ सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को तुरन्त केन्द्रीय पुलिस की दो और कंपनी भेजने के आदेश दिये।

को और भाजपा शासित त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया कि मतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

कोर्ट का आदेश विपक्षी पार्टियों, जिनमें तृणमूल भी शामिल है, के इन दावों के बीच आया है कि भाजपा कार्यकर्ता उनके प्रत्याशियों को धमका रहे हैं और मतदाताओं को मतदान केन्द्र नहीं जाने दे रहे हैं। नकाबपोश धारी लोगों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से मिलने से इंकार किया

सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के "फ्लोर नेताओं" की बैठक में वातावरण ममता बनर्जी के खिलाफ था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवम्बर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस प्रकार कांग्रेस नेताओं को तोड़कर अपनी तृणमूल कांग्रेस को ताकत बढ़ा रही हैं उसकी वजह से नाराज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ममता के इस सप्ताह के दिल्ली प्रवास के दौरान उनसे मिलने से मना कर दिया। किन्तु ममता ने सोनिया के इंकार को कोई खास महत्व न देते हुये कहा कि जरूरी नहीं है कि वे (ममता) जब भी दिल्ली आयें तो हर बार सोनिया से मिलें।

तृणमूल और कांग्रेस के बीच तनावपूर्ण समीकरणों के चलते, सोनिया ने वरिष्ठ पार्टी नेता कमलनाथ तथा आनन्द शर्मा के साथ अलग-अलग मीटिंग की, ताकि यह पता लगे कि आखिर ममता क्या चाहती हैं, क्योंकि उनकी करतूतें उस विपक्षी एकता में दूरार डाल रही हैं, जिसकी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में अत्यधिक जरूरत है ताकि कृषि कानूनों को रद्द किये जाने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा जा सके।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि सोनिया, ममता से इसलिये भी रुठ हैं कि वे बुधवार को यहां भाजपा नेता डॉ. सुब्रह्मन्यम स्वामी (82) के साथ एक किस्म का मेल-जोल दिखा रही थीं, हालाँकि उन्होंने आनन्द शर्मा के माध्यम से सोनिया तक यह बात पहुँचा दी थी कि डॉ. स्वामी खुद मिलने आए थे,

■ पर, राहुल गांधी ने समझाने-बुझाने का काम किया और कहा कि, अभी भाजपा के खिलाफ एक जुट होकर लड़ने का समय है, अतः ममता द्वारा चुभोई जा रही सुई से ज्यादा विचलित न हों। केवल भाजपा को हराने के लिए पूर्ण प्रयास करें, छोटी-छोटी बातों से विचलित न हों।

तथा उन्हें कभी भी अपनी तृणमूल कांग्रेस में लेने का प्रश्न ही नहीं है।

सोनिया गांधी ने गुरुवार शाम को अपने निवास 10, जनपथ पर एक रणनीतिक मीटिंग ली। सोनिया की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में उन मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन पर संसद सत्र में ध्यान केन्द्रित करना होगा। मीटिंग में राहुल गांधी की समझदारी भरी यह बात छाई रही कि हो सकता है कि विपक्षी दलों के सिद्धान्त तथा रुख भिन्न हों, लेकिन सभी विपक्षी दलों का कॉमन लक्ष्य है- आपस में नहीं, भाजपा से लड़ना।

कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन के रूप में, सोनिया गांधी ने संसद के दोनों सदनों के पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। नेतागण इस बात पर सहमत थे कि कांग्रेस नेताओं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संधू के खिलाफ केस वापस

जयपुर, 25 नवम्बर (का.सं.)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत एकल पट्टा प्रकरण से जुड़े मामले में पूर्व आईएसएस जोएस संधू और पूर्व आरएसएस निष्काम दिवाकर सहित आरएसएस औरका मल सैनी के खिलाफ केस वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी पर शुक्रवार को फैसला देगी। राज्य सरकार की ओर से पेश अर्जी

■ राज्य सरकार ने ए. सी. बी. मामलों की विशेष अदालत में संधू सहित तीन अफसरों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार का केस वापस लेने की अर्जी दी है, जिसका शुक्रवार को फैसला होगा।

में कहा गया कि राज्य स्तरीय कमेटी ने इन तीनों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश की है। एसीबी ने भी अनुसंधान में माना है कि मामले में निवासित भूमि सरकारी नहीं है। ना तो मूल पट्टेधारियों और ना ही राज्य सरकार या जेडीए ने एसीबी में कोई शिकायत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्या हर दिल्ली यात्रा के दौरान सोनिया गांधी से मिलना संवैधानिक अनिवार्यता है'

ममता बनर्जी का एक पत्रकार के सवाल पर यह तीखी प्रतिक्रिया देना, शायद संकेत है कि अगले आम चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन की संभावना नहीं है

-अंजन राँच-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवम्बर। अब यह अधिकारिक हो गया है। तृणमूल कांग्रेस वर्ष 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में औपचारिक रूप से कांग्रेस से संबंध तोड़ रही है, यह बात तब साफ हो गई, जब ममता बनर्जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संवाददाता से पलटकर प्रश्न किया: क्या सोनिया गांधी से भेंट करना अनिवार्य है? क्या यह एक संवैधानिक जरूरत है? उन्होंने जिस उत्साह के साथ यह विपरीत प्रश्न-पूछा, उससे अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के विपक्ष में कांग्रेस के प्रति उनकी नापसंदगी प्रदर्शित होती है। लेकिन इसी दौरान उनकी टीम

मेघालय में नेताओं का दलबदल करवाने के काम में जोर-शोर से लगी हुई थी, जो बाद में सामने आ गया। आज, गुरुवार को ममता ने सबसे क्रूरतम प्रहार किया। तृणमूल कांग्रेस ने मेघालय के कांग्रेस विधायकों का एक बड़ा दल-बदल करवाया। मेघालय में, कांग्रेस अब तक मुख्य विपक्षी पार्टी थी। अब कांग्रेस के 12 विधायकों में तृणमूल में शामिल हो जाने के बाद, यहां तृणमूल मुख्य विपक्षी दल बन गया है। यह उसकी तस्वीर है, जिसके बारे में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी एक लम्बे अर्से से सोचती रही हैं। मेघालय में मुख्य विपक्षी दल बनने के बाद ममता को अब यह कलंक नहीं होना पड़ेगा कि उनकी पार्टी सिर्फ पश्चिम

■ इसी संदर्भ में मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों को तृणमूल ने अपनी पार्टी में शामिल किया।

■ यह घटनाक्रम ममता बनर्जी का राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की दिशा में ठोस कदम है, पर इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा।

■ अब इस घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी की विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरने की संभावना भी खत्म हो गयी।

■ इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष का भाजपा के खिलाफ संगठित होने का "चांस" भी अगर खत्म हो जाता है, तो इसका सीधा लाभ भाजपा को ही मिलेगा।

बंगाल तक सीमित एक राज्य स्तरीय पार्टी मात्र है।

इस घटनाक्रम का परिणाम यह है कि अगले लोकसभा चुनावों से पूर्व

भाजपा को अधिकतम राजनीतिक बहुत सुनिश्चित हो गयी है। वास्तव में वे देश में कहीं भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के उद्देश्य को लेकर चलती रही हैं। उनका उद्देश्य कांग्रेस को तबाह कर उसका स्थान ग्रहण करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से देखा

जा सकता है कि, ममता बनर्जी को संभवतः विपक्षी एकता के चेहरे के रूप में आत्मसात नहीं किया जाएगा। लेकिन अन्ततः वे एक ऐसी राज्य स्तरीय नेता बनकर रह जाएंगी जिनका अन्य कहीं भी जनाधार नहीं होगा। भाजपा के मजबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मजबूत प्रदर्शन टी.एम.सी. के नॉर्थ इंडिया में पैर जमाने की संभावना पहले ही खत्म कर देगा। अशोक तंवर कोई वास्तविक नई शुरुआत करने के बजाए राहुल गांधी द्वारा साइड लाइन किए जाने के कारण एक बार फिर से बैरभाव दर्शा रहे हैं। बिहार में जद (यू) के पूर्व नेता अपनी पसंद की पार्टी में पृष्ठभूमि में धकेल दिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)